RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 13 DECEMBER TO 19 DECEMBER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 12 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

वित्त वर्ष 24 में जीएसटी कलेक्शन से मालामाल हो जाएगी सरकार Page 3

श्रीलंका को फिर मिली IMF से सहायता Page 4

भारतीय वैज्ञानिकों ने शरीर की कोशिकाओं में छिपे कोरोना वायरस के भंडार का पता लगाया Page 5

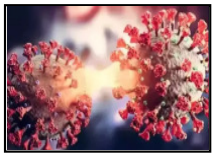

editoria!

अर्थव्यवस्था का विस्तार

एक ओर जहां बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर पर कई कारणों से ग्रहण लग रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. वैश्विक निवेशकों के भारत में बढ़ते भरोसे से अर्थव्यवस्था को ठोस आधार भी मिल रहा है. हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुल बाजार पूंजी चार ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है. हमारी अर्थव्यवस्था भी चार ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने से कुछ ही दूर है. ऐसे में पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जल्दी ही पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के आधार पर भारत पांचवें पायदान पर पहले ही पहुंच चुका है. वैश्विक निवेशक आम तौर पर अमेरिका, यूरोप, चीन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं. वृद्धि के मामले में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है. निवेशकों के भारत में बढ़ते भरोसे का प्रमुख कारण राजनीतिक स्थिरता है. इससे नीतिगत स्थिरता बनी रहती है. दूसरा कारण आर्थिक सुधार हैं, जिनके कारण कारोबारी सुगमता आयी है तथा पारदर्शिता बढ़ी है. रिजर्व बैंक के रूप में हमारे पास एक मजबूत केंद्रीय बैंक है तथा बैंकिंग प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है. यह तीसरी वजह है. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कल्याणकारी योजनाओं तथा तकनीक पर ध्यान देने से खर्च में बढ़ोतरी स्वाभाविक है. इसके बावजूद सरकारी कर्ज जीडीपी का लगभग 82 प्रतिशत है, जबकि अनेक विकसित और विकासशील देशों में यह आंकड़ा सौ फीसदी से ज्यादा हो चुका है. सरकार ने देशी-विदेशी बाजार के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना का लाभ दिखने लगा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पाद, इंजीनियरिंग, मशीनरी आदि के क्षेत्र में निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना काल में पैदा हुई स्थितियों, आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध तथा भू-राजनीतिक आशंकाओं को देखते हुए कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चीन के विकल्प तलाश रही हैं. इसका बड़ा फायदा भारत को मिला है. सभी कारक इंगित कर रहे हैं कि प्रगति की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ती जायेगी और भारत आगामी आठ-दस वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा. शेयर बाजार की पूंजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है. उल्लेखनीय है कि अच्छे मुनाफे के बावजूद उस अनुपात में घरेलू उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं. डिजिटल तकनीक तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति उत्साहजनक है, पर इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को एक छलांग मिल सके.

भारत ने रूस से खरीदा 10 माह में सबसे महंगा तेल

स्पाइसजेट को 446 करोड़ रुपये का घाटा

सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अब रूस से महंगे भाव पर क्रूड खरीद रहा है। अक्तूबर में भारत ने 84.20 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर कच्चा तेल खरीदा है। दिसंबर, 2022 के बाद 10 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर में क्रूड का भाव 81.24 डॉलर प्रति बैरल था। हालांकि, यह इराक से 85.97 डॉलर और सऊदी अरब से 98.77 डॉलर प्रति बैरल की दर से खरीदे तेल से फिर भी सस्ता है। ओपेक देशों ने रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा लगाई है।?

औद्योगिक उत्पादन 16 माह के उच्च स्तर पर

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अक्तूबर, 2023 में बढ़कर 16 महीने के उच्चस्तर 11.7 फीसदी पर पहुंच गई। विनिर्माण, खनन एवं बिजली क्षेत्रों के शानदार प्रदर्शन से यह तेजी देखने को मिली है।?एक साल पहले की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 4.1 फीसदी की गिरावट रही थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले जून, 2022 में आईआईपी में सर्वाधिक 12.6 फीसदी तेजी दर्ज की गई?थी।?आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 10.4 फीसदी बढ़ा। एक साल पहले की समान अवधि में इसमें 5.8 फीसदी की गिरावट रही थी। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 13.1 फीसदी रही, जबकि एक साल पहली की समान अवधि में यह 2.6 फीसदी रही थी। बिजली क्षेत्र में 20.4 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों यानी अप्रैल-अक्तूबर अवधि में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6.9 फीसदी पर पहुंच गई। पिछले साल की समान अवधि में यह 5.3 फीसदी रही थी।

कोल इंडियाः निवेश 7.6 फीसदी बढ़ा

कोल इंडिया का निवेश चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में 7.6 फीसदी बढ़कर 10,492 करोड़ पहुंच गया। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को बताया, एक साल पहले यह 9,751 करोड़ रुपये था। घरेलू कोयला उत्पादन में इसका हिस्सा 80 फीसदी है।

स्पाइसजेट को 446 करोड़ रुपये का घाटा

स्पाइसजेट को सितंबर तिमाही में 446 करोड़ का घाटा हुआ है। एक साल पहले 830 करोड़ का घाटा हुआ था। इस दौरान राजस्व 27 फीसदी गिरकर 1,429 करोड़ रहा। उधर, कंपनी के बोर्ड ने शेयरों के जरिये 2,250 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है।

फॉक्सवैगन जनवरी से 2% बढ़ाएगी दाम

फॉक्सवैगन एक जनवरी से कारों की कीमतों में दो फीसदी बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि लागत बढ़ने से उसे दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। उधर, स्कोडा ने भी एक जनवरी से अपने वाहनों की कीमतें 2 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है।

डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 83.40 पर बंद हुआ

इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ना महंगा

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.40 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 5 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.39 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। कच्चा तेल 76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। मंगलवार को रुपया 83.38 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस वित्त वर्ष अब तक रुपया 1.22% तक कमजोर हुआ

चालू वित्त वर्ष (2023-24) में रुपया करीब 1.22ङ्ग तक कमजोर हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में रुपया 82.39 रुपए प्रति डॉलर पर था, जो अब 83.40 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया है।

इंपोर्ट करना होगा महंगा

रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा अमेरिका में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में 1 डॉलर मिल जाते थे। अब 1 डॉलर के लिए छात्रों को 83.40 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना और खाना और अन्य चीजें महंगी हो जाएंगी।

करेंसी की कीमत कैसे तय होती है?

डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिशिएशन। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिससे वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है। फॉरेन रिजर्व के घटने और बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर दिखता है।

अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर, अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर होगा तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा। इसे फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं।

अब सस्ता होगा देश में पेट्रोल-डीजल!

रिलायंस के रास्ते पर चली यह सरकारी कंपनी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पिछले साल मई के पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी ही यह स्थिति बदल सकती है। इसकी वजह यह है कि सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वेनेजुएला से तेल मंगाने की तैयारी में है। अमेरिका ने अक्टूबर में वेनेजुएला पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था। उसके बाद से कई भारतीय कंपनियां वहां से तेल मंगा रही हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल शामिल हैं। इन कंपनियों ने वेनेजुएला से तेल मंगाने के लिए कार्गो बुक किए हैं। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले वह वेनेजुएला से काफी तेल मंगाता था।

बीपीसीएल के रिफाइनरीज प्रमुख संजय खन्ना ने बुधवार को कहा कि कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी की रिफाइनरियां वेनेजुएला के तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हैं और हमने अपने इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट को इसके लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वेनेजुएला से होने वाले आयात से रूसी इम्पोर्ट पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका ने साल 2019 में वेनेजुएला पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है।

वेनेजुएला से तेल का आयात

वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले भारत वेनेजुएला से हर महीने एक करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदता था। साल 2018-19 के दौरान रिलायंस हर महीने वेनेजुएला से पांच बड़े टैंकर कच्चा तेल खरीदती थी। हाल में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल मंगाने के लिए तीन टैंकर बुक किए हैं। ये अगले कुछ दिनों में भारत पहुंच सकते हैं। इनमें 60 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जाने की क्षमता है। वेनेजुएला पर पाबंदी लगने से पहले रिलायंस और नयारा एनर्जी नियमित रूप से वहां से तेल खरीदती थीं। अमेरिकी पाबंदी के बावजूद चीन की कंपनियां वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीद रही थीं। लेकिन पाबंदियां हटने के बाद यह छूट कम हो गई है। इसकी वजह यह है कि दूसरे कई देशों ने भी वेनेजुएला से खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है। वेनेजुएला दूसरे देशों को भी कच्चा तेल देने का इच्छुक है। हाल में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि भारत डिस्काउंट पर वेनेजुएला से तेल खरीदने का इच्छुक है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है लेकिन 85% से ज्यादा मांग की पूर्ति आयात से होती है।

कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत

पिछले दो साल में कच्चे तेल की कीमत में भारी उतारचढ़ाव आया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह 139 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था। इस बीच भारत को रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा था लेकिन हाल के दिनों में इसमें भी गिरावट आई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड 0.23₹ की गिरावट के साथ 73.01 डॉलर पर चल रहा है जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 0.21₹ की गिरावट के साथ 68.40 डॉलर पर है। इस बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है।

RBI ने लिया बड़ा फैसला

अब बैंकों को बढ़ाना होगा सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

RBI ने मौजूदा एमपीसी पर एक बड़ी बैठक करते हुए आखिरी फैसला ले लिया है जिसके अंदर सभी बैंकों को बताया गया है कि उन्हें अपने सेविंग अकाउंट के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। वरना आगे उनके ऊपर बड़ा एक्शन ले सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस की लागू होती है। आरबीआई पहले ही मौद्रिक नीति समिति बना चुका है और अब आरबीआई ने इस पर एक आखरी फैसला ले लिया है,

जिसके अंदर बताया गया कि सभी बैंकों को अपने बचत खातों के ऊपर दिए जाने वाले ब्याज के अंदर बढ़ोतरी करनी होगी। जिसके ऊपर आरबीआई ने कहा है कि अगर बैंक खाते के अंदर रु. 100000 जमा है तो उसे पर बैंक को 6% वार्षिक ब्याज देना होगा।

यूनिटी बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा पर प्रति वर्ष 9.50% की उच्च ब्याज दर प्रदान करता है, जबकि सामान्य ग्राहकों को प्रति वर्ष 9% की कम ब्याज दर मिलती है। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड दोनों वाणिज्यिक बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक की। संभावना है कि समिति रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करेगी, जो पिछली चार मौद्रिक नीति समीक्षाओं से अपरिवर्तित बनी हुई है। रेपो रेट आखिरी बार फरवरी में घटाकर 6.5₹ किया गया था।

पीएफ कर्मचारियों को अब हर महीना मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट जॉब करते हुए पीएफ का पैसा कट रहा है तो फिर ऐसे कर्मचारियों के लिए कई धाकड़ स्कीम चलाई जा रही हैं। हम आपको अब एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद हर महीना के हिसाब से पेंशन का लाभ दिया जा जाएगा।

आप इस बाच को सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन सौ फीसदी सच है, क्योंकि अब पेंशन का लाभ आराम से दिया जाएगा जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार की तरफ से अब एंपलॉय पेंशन स्कीम(ईपीएस) चलाई जा रही है, जो कर्मचारियों के लिए किसी वरदान की तरह साबित होने वाली है।

इस स्कीम को ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है। इससे संगठित क्षेत्र में काम कर रिटायर्ड हो चुके लोगों को फायदा मिलता है। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो अब रिटायरमेंट के बाद आराम से हर महीना पेंशन का लाभ मिलेगा।

जानिए किन पीएफ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

ईपीएस स्कीम का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो काफी दिनों से पीएफ कटवा रहे हैं। जिसने मिनिमम 10 साल तक संगठित क्षेत्र में जॉब की है उसे पेंशन स्कीम का फायदा आराम से मिल जाएगा। इसमें योजना में नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का सामान योगदान करते हैं। कर्मचारी का योगदान पूरा हिस्सा ईपीएफ में आराम से जाता है। कंपनी के शेयर का 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में 3.67 फीसदी मंथली ईपीएफ में जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का आगाज साल 1995 में शुरू किया गया था, जो कर्मचारियों का दिल खुश करने करती दिख रही है।

इतनी आयु बाद मिलेगी पेंशन

ईपीएस का फायदा प्राप्त करने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप ईपीएफओ के सदस्य होना जरूरी है। मिनिमम दस साल तक नौकरी की हो। आपकी आयु 58 साल होनी चाहिए। आप 50 साल की उम्र होने पर ईपीएस से पैसा निकालने का काम शुरू कर सकते हैं। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15 हजार रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

वित्त वर्ष 24 में जीएसटी कलेक्शन से मालामाल हो जाएगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) बजट 2023 में तय लक्ष्य को पार कर सकता है। सरकार हर महीने जीएसटी कलेक्शन के शानदार आंकड़ों से बहुत उत्साहित है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 1 फरवरी, 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जीएसटी कलेक्शन के इभ्24 के टारगेट को संशोधित कर सकती हैं। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 13.32 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया था कि जुलाई 2017 में जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई थी। तब से जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है।

टारगेट से ज्यादा रहेगा कलेक्शन

अप्रैल में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ कलेक्शन

निर्मला सीतारमण ने 4 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा। इस वित्त वर्ष में हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। 1 दिसंबर को नवंबर के जीएसटी कलेक्शन के जीएसटी के आंकड़े जारी किए गए। नवंबर के जीएसटी कलेक्शन के आकड़े आने के बाद इस वित्त वर्ष हर महीने औसत जीएसटी कलेक्शन का भी पता चला है। यह 1.67 लाख करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह डेटा 1.51 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2021-2 में यह आंकड़ा 1.24 लाख करोड़ रुपये था। जिस साल जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई थी यानी वित्त वर्ष 2017-18 में यह सिर्फ 89,885 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन 9.57 लाख करोड़

दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े 1 जनवरी, 2024 को आएंगे। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अनुमान के मुकाबले ज्यादा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6 फीसदी रही। रिजर्व ने दिसंबर की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। इसका असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ने की उम्मीद है। इस वित्त वर्ष जीएसटी कलेक्शन बजट में तय लक्ष्य से पार कर जाने की उम्मीद है। बजट 2023 में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन 12 फीसदी (वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले) ज्यादा रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन 9.57 लाख करोड़ रुपये था।

टारगेट से 80,000 करोड़ ज्यादा रह सकता है कलेक्शन

जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटिग्रेटेग जीएसटी से होने वाला कलेक्शन शामिल है। सेंट्रल जीएसटी को ण्उएऊ कहा जाता है। इससे होने वाला कलेक्शन कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। स्टेट जीएसटी कलेक्शन से मिला पैसा राज्यों को जाता है। इंटिग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन से मिला पैसा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच हर महीने बंट जाता है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि इस वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी कलेक्शन तय लक्ष्य से 80,000 करोड़ रुपये ज्यादा रह सकता है।

आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने का एक और मौका

UIDAI ने बढ़ाई डेडलाइन

नई दिल्ली। एजेंसी

UIDAI ने माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार डिटेल्स के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। डिटेल्स के मुताबिक, 'निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, इस सुविधा को 3 और महीनों के लिए यानी 15.12.2023 से 14.03.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।'

अगर आपने अभी तक अपने आधार को अपडेट नहीं किया है तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आपके लिए एक और मौका लाया है।यूआईडीएआई ने आधार मुफ्त में अपडेट करने के लिए आपको 3 और महीने का समय दिया है। यूआईडीएआई ने माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार डिटेल्स के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। डिटेल्स के मुताबिक, 'निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, इस सुविधा को 3 और महीनों के लिए यानी 15.12.2023 से 14.03.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

क्यों अपडेट करना चाहिए आधार?

अगर आपका पता अपडेट नहीं है, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 10 नवंबर, 2022 को पीआईबी के एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. यह निवासियों से अपने दस्तावेजों को अपडेटेड करने का आग्रह करता है। हाल ही में जारी गजट अधिसूचना में भी साफ-साफ कहा गया है कि निवासी हर 10 साल पूरे होने पर ऐसा कर सकते हैं। आधार में दस्तावेजों को अपडेट रखने से जीवन को आसान बनाने, बेहतर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलती है. इसके अलावा इससे सटीक ऑथेंटिकेशन सक्षम होता है।

श्रीलंका को फिर मिली IMF से सहायता

अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए देगा 33.7 करोड़ डॉलर

कोलंबो। एजेंसी

आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने फैसला लिया है कि नकदी संकट से जूझ रहे देश को व्यापक आर्थिक व ऋण स्थिरता बहाल करने के लिए करीब 33.7 करोड़ डॉलर की सहायता दी जाएगी। श्रीलंका पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में आर्थिक संकट के कारण भोजन, बिजली और ईंधन की कमी हो गई है। पिछले साल श्रीलंका अपने कर्ज चुकाने के दायित्वों से चूक गया, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ उसे तीन अरब यूरो का बेलआउट सौदा करना पड़ा था। अब एक बार फिर देश ने आईएमएफ की ओर सहायता की नजर से देखा है।

करीब 33.7 करोड़ डॉलर की सहायता

इसी को लेकर आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका के साथ 48 महीने की विस्तारित कोष सुविधा के तहत पहली समीक्षा पूरी कर ली है। साथ ही फैसला लिया है कि नकदी संकट से जूझ रहे देश को व्यापक आर्थिक व ऋण स्थिरता बहाल करने के लिए करीब 33.7 करोड़ डॉलर की सहायता दी जाएगी।

गोपनीय आधार पर किया गया ऋण पुनर्गठन

श्रीलंका के वरिष्ठ मिशन प्रमुख पीटर ब्रेउर ने बताया कि आईएमएफ द्वारा 2.9 अरब डॉलर जारी करने की पहली समीक्षा को समाप्त करने के लिए चीन के साथ ऋण पुनर्गठन का काम बहुत ही गोपनीय आधार पर किया गया। श्रीलंका ने चीन से काफी कर्ज लेकर रखा है। उसे अपने कुल ऋण का 52 प्रतिशत हिस्सा चीन को देना है।

दूसरी किश्त जारी

ब्रेउर ने मंगलवार को बताया, 'सैद्धांतिक रूप से चीनी समझौता श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन वार्ता के लिए बेहद अच्छी खबर है। हमने अधिकारियों द्वारा गोपनीय आधार पर साझा किए गए समझौते की शर्तों का पढ़ा है।' आईएमएफ ने मंगलवार देर रात समीक्षा पूरी की और द्वीप राष्ट्र को 33.7 करोड़ डॉलर की दूसरी किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी। इससे चार साल की सुविधा में संवितरण मूल्य 67 करोड़ डॉलर हो गया।

फॉक्सकॉन को एप्पल इंडिया प्लांट में 1 अरब डॉलर और निवेश करने की मंजूरी मिली : रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

ताइवानी अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन को भारत में एक संयंत्र में कम से कम 1 बिलियन डॉलर और निवेश करने की मंजूरी मिल गई है जो एप्पल उत्पादों का निर्माण करेगा। यह चीन के बाहर एक केंद्र स्थापित करने के उनके लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।ब्लूमबर्ग ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि फॉक्सकॉन का इरादा बेंगलुरु हवाई अड्डे के करीब 300 एकड़ की साइट के लिए पहले निर्धारित 1.6 बिलियन डॉलर के अलावा स्वीकृत राशि खर्च करने का है। नई राशि संभवतः आईफोन सहित एप्पल उपकरणों के लिए अतिरिक्त क्षमता को नियंत्रित करेगी।

खर्च की हालिया मंजूरी के साथ, ताइवानी फर्म ने साइट के लिए लगभग 2.7 बिलियन डॉलर आवंटित किए। एप्पल के प्रमुख विनिर्माण भागीदार, फॉक्सकॉन ने फैक्ट्री के लिए अपना बजट बढ़ाया है। इसकी शुरुआत 2023 की शुरुआत में कॉम्प्लेक्स में केवल 700 मिलियन डॉलर का निवेश करने के इरादे से हुई थी, जो कर्नाटक में स्थित है।

इस बीच, टाटा समूह तमिलनाडु के होसुर में भारत के सबसे बड़े आईफोन असेंबली प्लांट में से एक बनाने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस सुविधा में लगभग 20 असेंबली लाइनें होने और दो साल के भीतर 50,000 कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह साइट 12 से 18 महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। इस कदम को दक्षिण एशियाई देश में विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के एप्पल के उद्देश्य का हिस्सा माना जाता है। टाटा पहले से ही कर्नाटक में आईफोन विनिर्माण इकाई संचालित करता है, जिसे उन्होंने विस्ट्रॉन कॉर्प से खरीदा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगा हुआ कच्चा तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार 13 दिसंबर के लिए देश में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत तेल कंपनियों ने जारी कर दी है। एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड कल 0.39 प्रतिशत चढ़कर 76.33 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। हालांकि भारत की तेल कंपनियों ने लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी कर दिया है। तेल कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं।

भारत में क्षमता व नवाचार केंद्रों का बाजार 2027 तक 117 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगाः रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

भारत में क्षमता व नवाचार केंद्रों का बाजार आकार वर्तमान में 65 अरब अमेरिकी डॉलर से करीब दोगुना होकर 2027 तक 117 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाली इकाइयों को सीआईएच (क्षमताएं व नवाचार केंद्र) कहा जाता है। परामर्श कंपनी बीसीजी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, घरेलू सीआईएच बाजार 2027 तक 16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है। यह वर्तमान 65 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2027 में 117 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस बीच, रिपोर्ट में 2027 तक वैश्विक सीआईएच खर्च की वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से बढ़कर 715 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्तमान में 475-515 अरब अमेरिकी डॉलर है। बीसीजी रिपोर्ट अक्टूबर में 50 कंपनियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।

मेक इन इंडिया पर जोर के बावजूद हर दूसरे भारतीय ने खरीदा मेड इन चाइना सामान

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पर काफी जोर दे रही है। हालांकि उसके बाद भी देश के बाजारों में चीन के सामानों की खपत खूब हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आधे से ज्यादा भारतीयों ने पिछले एक साल के दौरान कोई न कोई मेड इन चाइना सामान जरूर खरीदा है।

लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के साथ हुए सीमाई विवाद ने भारतीयों की धारणाओं को प्रभावित किया है। पिछले 12 महीने में बहुत सारे लोगों ने चीनी सामानों से दूरी बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, 45 फीसदी भारतीयों ने पिछले एक साल में कोई भी मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदा है।

इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल एक्सेसरीज टॉप पर

भारतीयों की ओर से खरीदे जा रहे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को देखें तो इस मामले में टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल एक्सेसरीज हैं। लोकल सर्कल्स को सर्वे में 56 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले 12 महीने के दौरान मेड इन चाइना गैजेट यानी स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक जैसे प्रोडक्ट की खरीदारी की है। वहीं 49 फीसदी लोगों ने चीन में बने वाटर मन फेस्टिवल लाइटिंग, लैम्प, कैंडल जैसे प्रोडक्ट की खरीदारी की।

सर्वे में 33 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले एक साल में चीन में बने खिलौने और स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदा है। 29 फीसदी लोगों ने गिफ्ट आइटम खरीदने, 26 फीसदी ने टेलीविजन, एयर प्यूरिफायर, केतली जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को खरीदने और 28 फीसदी ने लाइटिंग व फर्नीचर जैसे होम प्रोडक्ट खरीदने की बात स्वीकार की है। इस दौरान 15 फीसदी लोगों ने मेड इन चाइना फैशन प्रोडक्ट पर और 15 फीसदी ने अन्य प्रकार के सामानों पर पैसे खर्च करने की बात की है।

चीनी सामानों से दूरी बनाने की सबसे बड़ी वजह सीमाई विवाद

चीनी सामानों से दूरी बनाने की सबसे बड़ी वजह सीमाई विवाद है। इनका हिस्सा 3 फीसदी है। वहीं 16 फीसदी लोगों ने सस्ते में भारतीय सामान उपलब्ध होने के कारण दूरी बनाने की बात कही। सर्वे में शामिल 16 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस के चलते चीनी सामानों के ऊपर भारतीय सामानों को तरजीह दी है।

16 फीसदी ने खोज निकाला भारतीय विकल्प

रिपोर्ट के अनुसार 63 फीसदी भारतीयों ने भू-राजनीतिक तनाव के चलते मेड इन चाइना सामने से दूरी बनाने की बात की है। उनका कहना है कि उन्होंने मेड इन चाइना सामानों की खरीदारी कम कर दी है। 16 फीसदी लोगों ने तो ये बताया कि उन्होंने चीनी समानों का भारतीय विकल्प खोज निकाला है, जो सस्ता भी है और क्वलिटी में भी बेहतर है।

भारत वैश्विक वित्तीय सेवा बाजार का केंद्र बन सकता है: श्री धर्मेन्द्र प्रधान

हम ज्ञान एवं दक्षता के एक सुपर हाईवे का निर्माण कर रहे हैं - श्री धर्मेन्द्र प्रधान

एआईसीटीई, एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व ने बैंकिंग, वित्त एवं बीमा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व एवं एआईसीटीई और बजाज फिनसर्व ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री; श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय; प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव, एआईसीटीई; श्री वेद मणि तिवारी, सीईओ, एनएसडीसी तथा एमडी, एनएसडीसी इंटरनेशनल एवं संजीव बजाज, अध्यक्ष तथा एमडी, बजाज फिनसर्व की गरिमामय उपस्थिति में दो समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। समारोह में कुरुश ईरानी, अध्यक्ष ग्रुप - सीएसआर एवं पल्लवी गांधीकर, राष्ट्रीय प्रमुख - सीएसआर, बजाज फिनसर्व भी उपस्थित थे।

एआईसीटीई, (उच्च शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), (कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में), देश में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख वास्तुकारों ने युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों हेतु तैयार करने के लिए आज भारत के अग्रणी एवं सबसे विविध वित्तीय सेवा समूह बजाज फिनसर्व लिमिटेड के साथ साझेदारी की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने हेतु बजाज फिनसर्व के साथ एनएसडीसी और एआईसीटीई के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का साक्षी बनने की और बैंकिंग, वित्त एवं बीमा में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के शुभारंभ पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, आज जो यह साझेदारियां बनी है वह वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दक्षताओं का निर्माण करेंगी और हमारे युवाओं को वित्तीय तथा डिजिटल क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाएंगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत का विजन, कल लॉन्च किया गया वॉयस ऑफ यूथ कार्यक्रम विकसित भारत के लिए युवाओं के विचारों, विकसित भारत के निर्माण में कौशल विकास और वित्तीय क्षेत्र की भूमिका को उजागर करता है। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे युवा ज्ञान, दक्षता, कौशल और सही प्रवृति द्वारा संचालित विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ज्ञान और दक्षता का एक सुपर हाईवे बना रहे हैं और भारत वैश्विक वित्तीय सेवा बाजार का केंद्र बन सकता है।

प्रो. टी.जी. सीतारम, अध्यक्ष, एआईसीटीई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, बजाज फिनसर्व के साथ साझेदारी से शिक्षा एवं उद्योग-अकादमिक संबंधों में नए सहयोग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह वित्त, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में छात्रों के लिए शिक्षा, इंटर्नशिप और जॉब प्रशिक्षण के विशाल अवसर प्रदान करके उद्योग और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने के एआईसीटीई के लक्ष्य को मजबूत करेगा।

एनएसडीसी के सीईओ एवं एनएसडीसी इंटरनेशनल के एमडी वेद मणि तिवारी ने कहा, भारत के वित्तीय क्षेत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास देखी गई है। उन्होंने कहा, एनएसडीसी में, हमारा समर्पण कौशल विकास पहल के माध्यम से विविध अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने में निहित है, और बजाज फिनसर्व के साथ साझेदारी उद्योग के वित्तीय क्षेत्र में बदलाव के साथ हमारे कौशल प्रयासों को संरेखित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, संजीव बजाज ने कहा कि एनएसडीसी और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से हम युवाओं को कौशल प्रदान कर सकेंगे और इसके माध्यम से बदलाव ला सकेंगे, जिससे सफलता के अनंत रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक लचीलापन और कौशल भारत, कुशल भारत की थीम के अनुरूप भविष्य के लिए एक समावेशी श्रमबल का निर्माण भी करेगा।

भारतीय वैज्ञानिकों ने शरीर की कोशिकाओं में छिपे कोरोना वायरस के भंडार का पता लगाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

अनुसंधानकर्ताओं ने शरीर की कोशिकाओं के अंदर कोरोना वायरस (सार्स कोव-2 वायरस) के छिपे संभावित भंडार की पहचान की है जो कोविड-19 की निरंतरता और इससे फिर से संक्रमित होने पर प्रकाश डाल सकता है। नयी दिल्ली के यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बाह्यकोशिकीय पुटिकाओं (ईवी) यानी कोशिकाओं से निकले सूक्ष्मकणों का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण जानकारी सामने लायी।

उन्होंने कहा कि मानक आरटी-पीसीआर प्रक्रिया में जो व्यक्ति 'निगेटिव' पाये गये उनके ईवी में सार्स कोव-2 के आरएनए या आनुवांशकीय सामग्री पायी गयी। इस अध्ययन की मुख्य लेखिका सुकृति बावेजा ने कहा, '' ईवी में सार्स -कोव-2 आरएनए की पहचान एक ऐसी वैकल्पिक नैदानिक प्रविधि ढूंढ़ने की जरूरत पर बल देती है जो इस खोज का फायदा उठाये तथा कोविड-19 संक्रमण का और प्रभावी तरीके से पता लगाने एवं कोविड-19 से संक्रमण का प्रबंधन करने की हमारी क्षमता में संभावित क्रांति लाए।'' अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि पारंपरिक जांच में जो लोग इस वायरस (विषाणु) से मुक्त समझे जाते हैं , उनके सिलसिले में भी ईवी में सार्स कोव-2-आरएनए की मौजूदगी फिर संक्रमण होने के संभावित स्रोत का संकेत दे सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में इन संक्रमित ईवी ने पहले से अप्रभावित कोशिकाओं में इस विषाणु को पहुंचा देने की क्षमता प्रदर्शित की जबकि पहले संक्रमण के इस माध्यम की पहचान नहीं हो पायी थी। अनुंसधानकर्ताओं ने कहा कि 'लिवर रिसर्च' नामक एक विज्ञान पत्रिका में छपे इस अध्ययन से कोविड -19 का पता लगाने और उसका प्रंधन करने में सामने आ रही चुनौतियों से निपटने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है।

यूपीआई से अपने आप होगी 1 लाख तक की पेमेंट

बार-बार भुगतान करने वालों को होगी सुविधा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के जरिये ऑटोमेटेड पेमेंट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दिया है। इसके दायरे में म्यूचुअल फंड को भी शामिल किया गया है। अब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसे बार-बार होने वाले भुगतान, जिनमें 15,000 रुपये से ज्यादा जाने हैं, अपने आप अकाउंट से कट जाएंगे।

आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है, 'म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम के भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए एक लेनदेन की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।' नवंबर महीने में 11.23 अरब से अधिक लेनदेन के साथ यूपीआई आबादी के एक बड़े तबके के लिए डिजिटल भुगतान का पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है।

अभी कैसे होता है ऑटोमेटेड पेमेंट

ऑटोमेटेड पेमेंट की सुविधा अभी भी मौजूद है लेकिन इसके लिए तिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिथेंकेशन (AFA) की आवश्यकता होती है।आरबीआई ने पिछले हफ्ते ही ऑटोमेटड पेमेंट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पर विचार की बात कही थी। तब आरबीआई ने यूपीआई के जरिए कुछ कामों के लिए एक बार में ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ा दिया था।

घर में सुख समृद्धि लाता है मछलियों का जोड़ा

जो लोग किसी कारणवश एक्वेरियम में मछलियां न रख पाएं, उनके लिए मछलियों का प्रतीक चिन्ह फेंगशुई के अनुसार घर में रखना बेहद कारगर रहता है। धातु के बने मछली को कछुए के साथ घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। फेंगशुई के अनुसार मछली के जोड़े के प्रतीक चिन्ह को घर में लटकाने से घर के सदस्यों के ऊपर आने वाली विपत्तियां टलती हैं एवं घर में धन-संपत्ति के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। जिन परिवारों में अकारण तनातनी या क्लेश रहता है, वहां पर अगर बृहस्पतिवार के दिन धातु की सुनहरी मछलियों के जोड़ों का प्रतीक चिन्ह पूर्व-उत्तर दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं, में लटकाया जाए, तो परिवार के सदस्यों में सहनशक्ति में वृद्धि होती है, पारिवारिक झगड़े समाप्त होने लगते हैं। वातावरण में पर्याप्त शांति के लिए मछली के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मछली अपार सम्पति का सूचक होने के कारण इसके प्रतीक चिन्ह को अनादिकाल से सुख-समृद्धि के प्रतीक के रूप में अंकित किया जाता है। जहां ग्रहों के प्रभाव से घर-कार्यालय में मछलियों के जोड़े के प्रतीक चिन्ह को लटकाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं वास्तुशास्त्र एवं फेंगशुई के अनुसार मछलियों का जोड़ा घर-कार्यालय कीनकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा में परिवर्तित करता है, फलस्वरूप व्यक्ति की निर्णय क्षमता और मानसिक शक्ति बढ़ती है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

घर के सदस्यों को विपत्ति से बचाती है मछली

जल में रहने वाली मछली का प्रतिरूप आकाश में तारों के माध्यम से मीन राशि के रूप में प्रदर्शित होता है। तारों से मिलकर बनने वाली आकृति दो मछलियों के जोड़ों को दर्शाती है जिसे ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि की संज्ञा दी गई है। मीन राशि का नियंत्रण राशि स्वामी के रूप में देवताओं के गुरू बृहस्पति के पास है। देवगुरू बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति ज्ञानवान होकर सुख-समृद्धि, मान-सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है। शुभता के लिए मछली के जोड़े का प्रतीक चिन्ह बृहस्पतिवार के दिन घर-कार्यालय में टांगा जाए तो यह और भी प्रभावशाली परिणाम प्रदान करता है। वास्तु-फेंगशुई में मछली को खुशहाली से जोड़ा जाता है और यदि यह चिन्ह जोड़े में हो तो और भी अच्छा है। वास्तुशास्त्र के अनुसर मछली के जोड़े प्रतीक चिन्ह को सही दिशा में टांगने से सकारात्मक प्रभाव शीघ्र ही प्राप्त होने लगता है। पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा अथवा पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, ईशान कोण में मछली के जोड़ों को लटकाने से घर के सदस्यों का भाग्योदय, दुकान में लटकाने से दुकानदार की आय में वृद्धि होती है एवं कार्यालय में इसका प्रयोग उन्नतिकारक होता है।

धन और मछली का जोड़ा

धन लक्ष्मी जल की तरह चलायमान है, शास्त्रों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। मछली जल से जुड़ी होने के कारण एवं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का स्वरूप होने के कारण धन सम्पति को शीघ्र आकर्षित करती है। मछली का जोड़ा रूके या स्थगित कार्य को पानी के बहाव की तरह पूर्ण करने लगता है। मछली का जीवन जल से है, जब इसके प्रतीक को घर, दुकान, कार्यालय में वायु तत्व, हवा में लटकाया जाता है तो वायु तत्व के माध्यम से जल तत्व से संबंधित शांति, उस जगह की उर्जा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे वातावरण निरन्तर प्रगतिशील बना रहता है। हिन्दु धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि भगवान नारायण श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। धन की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए मछलियों की किसी भी प्रकार से सेवा अथवा मछलियों से सम्बन्धित उपाय करने से धन संबंधित भाग्य प्रबल होने लगता है। मछलियों के जोड़ा के शुभ प्रभाव के कारण घर-परिवार में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। भोजपत्र पर भगवान राम का नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाने की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। आप भी अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रतिदिन भोजनपत्र पर राम का नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर किसी आस-पास की नदी-तालाबमें अवश्य डालें।

जानें क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, हिंदू धर्म में क्यों है इसका विशेष महत्व

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

सनातन धर्म में जब भी देवी या देवता की मूर्ति घर या मंदिर में स्थापित की जाती है तो पूरे विधि-विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भी राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को हैं और इसके लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे। ऐसे में लोगों में मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक महत्व क्या है और यह क्यों किया जाता है।

जानें क्यों की जाती है प्राण प्रतिष्ठा

घर या मंदिर में जब भी किसी देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है तो मूर्ति को जीवित करने के अनुष्ठान को ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा-आराधना वास्तव में मूर्ति की नहीं, बल्कि उसमें निहित दिव्य शक्ति और चेतना की होती है।

प्राण प्रतिष्ठा मतलब ईश्वरत्व की स्थापना

किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से तात्पर्य उसमें ईश्वरत्व को स्थापित करने से है। जब भी किसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मंत्रों का जाप करने के साथ-साथ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।

घर में कभी नहीं रखते पत्थर की प्रतिमा

सनातन धर्म में यह भी मान्यता है कि घर में कभी भी पत्थर की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है क्योंकि पत्थर की मूर्ति की रोज पूजा की जाती है। पंडित प्रभु दयाल दीक्षित के मुताबिक, देव प्रतिमा की स्थापना हमेशा मंत्रोच्चार के साथ ही करना चाहिए।

ऐसे की जाती है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा

सबसे पहले देव प्रतिमा को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराएं।

मूर्ति को साफ मुलायम कपड़े से पोंछ लें।

प्रतिमा को सुंदर वस्त्र धारण कराएं और स्वच्छ जगह पर विराजित करें।

भगवान की प्रतिमा पर चंदन का लेप आदि लगाने के बाद फूलों से सिंगार करें।

बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा करें।

आखिर में देव स्तुति, आरती के बाद प्रसाद वितरण करें।

इन मंत्रों का करें जाप

ॐ मानो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं

तनोत्वरिष्टं यज्ञ गुम समिमं दधातु विश्वेदेवास इह मदयन्ता मोम्प्रतिष्ठ

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै

देवत्व मर्चायै माम् हेति च कश्चन

ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुप्रतिष्ठितो भव

प्रसन्नो भव, वरदा भव

टल जाते हैं दुर्घटना के योग, शनि की साढ़े साती चल रही है तो जरूर करें ये उपाय

हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। शनि देव व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि तीसरे, छठवें और 11वें घर में स्थित होता है तो शनि देव शुभ फल देते हैं। ज्योतिषीय के मुताबिक, जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती चलती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए।

शनिवार को पहने काले रंग के कपड़े

शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अपने सहयोगियों, नौकरों, श्रमिकों हमेशा खुश रखना चाहिए। इसके अलावा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।

शनिवार को न करें इन चीजों का सेवन

शनि की साढ़ेसाती चलने पर जातक को शनिवार को शराब, मछली, अंडा या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं शनिवार रात को दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार को रबर और लोहे से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।

सरसों के तेल व काली दाल का उपाय

शनिवार को शनिदेव को सरसों के तेल व काली दाल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान हनुमान की आराधना करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनिवार को दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

कुंडली में कर्ज से संबंधित दोष है तो 21 मंगलवार तक करें उपाय

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

आज के भौतिकवादी युग में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे तो जो किसी कर्ज के बोझ तले दबे न हो। अधिकांश लोगों पर ईएमआई का बोझ होता है। ऐसे में यदि आप भी अपना कर्ज का बोझ कम करना चाहते हैं और इस संकट को दूर करना चाहते हैं तो संकट मोचन भगवान हनुमान की आराधना जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता भी है कि भगवान हनुमान हर संकट से मुक्ति दिलाने वाले देवता है। पंडित चंद्रशेखर मलतारे के मुताबिक, ऋण मुक्ति के लिए महाबली हनुमान से जुड़े ये उपाय जरूर करना चाहिए।

21 मंगलवार हनुमान जी पूजा

हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में पूजा करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसे करने से कर्ज का बोझ जल्द दूर हो जाता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए।

मंगलवार को ऐसे करें हनुमान जी की पूजा

21 मंगलवार तक सुबह जल्दी स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को आसन पर रखें और मंगलवार को व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ करनी चाहिए।

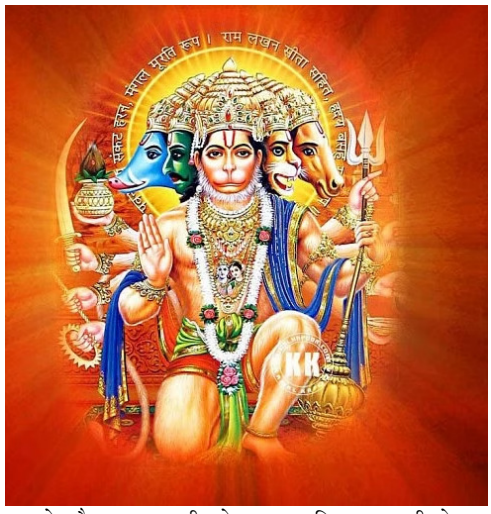

पूजा के दौरान हनुमान जी को लाल रंग के फूल, वस्त्र, सिन्दूर आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद आखिर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है।

हिकविजन इंडिया ने इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में नवीनतम उत्पाद प्रदर्शित किए

IDP-D5C, LCB और वीडियो इंटरकॉम उत्पाद पेश

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हिकविजन इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंफॉर्मा मार्केट्स द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस (आईएफएसईसी) के 16वें संस्करण में IDP-D5C, लेक्चर कैप्चर ब्रॉडकास्टिंग (LCB) सीरीज और वीडियो इंटरकॉम प्रोडक्ट्स के साथ नए AIoT उत्पादों और समाधानों का अनावरण किया है। श्री डी.आर. कार्तिकेयन, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक (मुख्य अतिथि) और आर. सत्यसुंदरम, आईपीएस, अतिरिक्त सीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस (सम्मानित अतिथि) इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अतिथि थे।दीप प्रज्ज्वलन समारोह और गणेश वंदना के बाद डी.आर. कार्तिकेयन ने अपने मुख्य भाषण में सभा को संबोधित किया, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा उत्पादों और उन्नत सुरक्षा समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है।

सबसे बड़े और सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए हिकविजन इंडिया बूथ ने इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस (आईएफएसईसी) में सुरक्षा उद्योग के पेशेवरों, अंतिम-उपयोगकर्ताओं और समझदार आगंतुकों को आकर्षित किया। इसके उन्नत सुरक्षा उत्पादों और समाधानों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। समझदार सुरक्षा पेशेवरों और आगंतुकों ने हिकविजन इंडिया बूथ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और आईओटी जैसी ट्रेंडिंग परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की।

इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के समृद्ध अनुभव पर बोलते हुए, आशीष पी. धकान, एमडी और सीईओ, प्रामा हिकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने कहा, 'हम इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2023 में अपने बूथ पर अग्रणी साझेदारों, अंतिम-उपयोगकर्ताओं और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ-साथ युवा आगंतुकों और नई संभावनाओं को देखकर खुश हैं। यह सुरक्षा उद्योग का 'कुंभ मेला' है। भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र भी। इस प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा उद्योग के साथियों, अंतिम-उपयोगकर्ताओं और भागीदारों से जुड़ना है। इस बार आईएफएसईसी नए प्रोडक्ट्स और फ्रिंज प्रोग्राम्स के कारण बेहद खास है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने अन्य नए उत्पादों के साथ इंटरएक्टिव डिस्प्ले पैनल (आईडीपी-डी5सी), लेक्चर कैप्चर ब्रॉडकास्टिंग (एलसीबी) सीरीज और न्यू वीडियो इंटरकॉम (वीडीपी) उत्पाद पेश किए हैं। हिकविजन इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज में नवीनतम तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया। हमने वीडियो सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल, घुसपैठ अलार्म, निरीक्षण और परिधि सुरक्षा खंडों में नवीनतम उत्पादों और समाधानों का अनावरण किया। हमने मोबाइल रोबोट उत्पाद, मशीन विजन उत्पाद और लॉजिस्टिक विजन सॉल्यूशंस भी प्रदर्शित किए।

2028 तक 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा भारत का ई-कॉमर्स बाजार

ग्रोथ में अमेरिका और चीन तक को छोड़ेगा पीछे

एजेंसी

भारत का ई-कॉमर्स बाजार जिस तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहा है, उसको देखते हुए साल 2028 तक इसके 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार 2023 में अनुमानित 57-60 बिलियन डॉलर से बढ़कर अगले 5 सालों में 160 बिलियन डॉलर पर जाने की उम्मीद है। बैन एंड कंपनी की 'द हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में जबरदस्त तेजी आई है जिससे ये आंकड़ा हासिल करना आसान होगा।

8-12 बिलियन डॉलर हर साल बढ़ रहा ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग का बाजार

साल 2020 के बाद से भारत के ऑनलाइन रिटेल बाजार में हर साल लगातार 8-12 बिलियन डॉलर का एक्सपेंशन यानी विस्तार हुआ है। ई-कॉमर्स मार्केट में कस्टमर के खर्चों के पैटर्न पर नजर रखने वाली बैन एंड कंपनी की ऑनलाइन 2023 रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आया है। बेन एंड कंपनी ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के साथ एक जॉइंट रिपोर्ट में कहा कि भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग बाजार के एक साल पहले की तुलना में 2023 में 17-20 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, हालांकि साल 2019-2022 के 25-30 फीसदी से तुलना करें तो ये धीमी गति है लेकिन इसके पीछे ऊंची महंगाई भी बड़ी वजह बनी है।

कोविड संकटकाल में प्रमुख रूप से बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी का समय ग्लोबल स्तर पर ई-रिटेल अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहा है। अभी भी कोविड संकटकाल की यादें ताजा हैं और पेनडमिक की वजह से सभी बाजारों में अलग-अलग स्तर पर ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ोतरी बनी हुई है।

देश के ऑनलाइन शॉपिंग बाजार की 5 अहम बातें

भारत में कोविड महामारी के बाद ई-रिटेल कारोबार में तेजी देखी गई है और लोग जमकर ऑनलाइन चीजें खरीद रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और चीन जैसे डेवलप बाजारों में, ई-रिटेल एंट्री में सालाना बढ़ोतरी महामारी से पहले के स्तर से थोड़ी कम रही है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद, भारत में कुल रिटेस खर्च में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी केवल 5-6 फीसदी पर ही है। भारत की तुलना में आर्थिक महाशक्ति अमेरिका में कुल रिटेल खर्च का 23-24 फीसदी और चीन में 35 फीसदी से ज्यादा ऑनलाइन है। परसेंटेज टर्म में देखें तो अगले 5 सालों में भारत के ई-कॉमर्स बाजार की ग्रोथ 166 फीसदी से ज्यादा बढ़ेगी।

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही

कई बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में बिजनेस की बढ़ती संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए यहां ऑनलाइन शॉपिंग इकोसिस्टम में निवेश बढ़ा रही हैं। इसमें अमेजॉन, वॉलमार्ट सपोर्टेड फ्लिपकार्ट के साथ-साथ रिलायंस रिटेल के अजियो जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में, अमेजन ने 2030 तक बाजार के लिए अतिरिक्त 15 बिलियन डॉलर लगाने का वादा किया. इसके बाद भारत में कंपनी का कुल निवेश 26 बिलियन डॉलर हो रहा है।

राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने की जरूरत - संयुक्त निदेशक उद्योग - इंदौर, मध्य प्रदेश सरकार

एसोचैम ने इंदौर में दो दिवसीय राष्ट्रीय आईपी (बौद्धिक संपदा अधिकार) यात्रा कार्यशाला का आयोजन किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एसोचैम की दो दिवसीय कार्यशाला - नेशनल आईपी यात्रा में संयुक्त निदेशक उद्योग - इंदौर म.प्र. सरकार, श्री एच.आर. मुजाल्दा ने सरकारी एमएसएमई योजनाओं और प्रोत्साहनों से उद्योग जगत आगे बढ़कर किस प्रकार से योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकता है इस संबंध में अंतर्दृष्टि के साथ पूरी जानकारी सबके समक्ष रखी। राज्य का उद्योग विभाग मध्य प्रदेश में एमएसएसई की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि और रोजगार अवसरों को बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि विभाग एमएसएमई को रिण, प्रौद्योगिकी और स्थानीय बाजारों के साथ साथ वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कराता है। उन्होंने बौद्धिक संपदा प्रबंधन के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि किस प्रकार यह किसी संगठन को अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में आईपीआर को बढ़ावा देना क्षेत्र के निरंतर विस्तार के लिये काफी महत्वपूर्ण है।

एसोचैम की मध्य प्रदेश राज्य विकास परिषद के सह-अध्यक्ष और भास्कर डेनिम के प्रबंध निदेशक श्री अखिलेश राठी ने अपने स्वागत संबोधन में बेहतर कारोबारी परिवेश की मजबूती के लिये बौद्धिक संपदा पर जोर दिया। आईपी फाइलिंग, राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग और निजी संस्थानों, संपत्ति दर्ज करने संबंधी शिक्षा और व्यवसायीकरण गतिविधियों के जरिये एमएसएमई को राष्ट्रीय आईपी यात्रा के लिये सशक्त बनाया जा रहा है। आईपी यात्रा एमएसएमई के लिये एक नवोन्मेषक के तौर पर आर्थिक वृद्धि बढ़ाने को प्रेरित करने की आकांक्षा है।

भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट और डिजाइन उप- नियंत्रक श्री योगेश बजाज ने पेटेंट प्रणाली के वाणिज्यिकरण पर जोर दिया। पेटेंट दर्ज करने के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शीर्ष राज्य हैं। बात जब ट्रेडमार्क आवेदन और आईपी फाइलिंग के होती है तो मध्य प्रदेश को इस मामले में बेहतर करने की जरूरत है।

कार्यशाला के दूसरे दिन - आईपीआर जागरूकता बढ़ाने में सरकार की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमता के इस युग में आईपीआर की भूमिका, राज्य स्टार्टअप नीति, नवोन्मेष के लिये आईपीआर रणनीति, एमएसएमई और स्टार्टअप, तथा शैक्षिक क्षेत्र में आईपीआर को लेकर जागरूकता बढ़ाने जैसे तकनीकी सत्रों पर गौर किया गया।

सीआईआई प्रेसिडेंट और महानिदेशक ने इंदौर में पहले सीआईआई केंद्र का उद्घाटन किया

सीआईआई सर्विसेज का हब बनेगा सीआईआई इंदौर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सीआईआई ने इंदौर में अपने पहले सीआईआई केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें सीआईआई की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय लीडरशिप मौजूद रही। यह सीआईआई केंद्र सभी सीआईआई सीओई (सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज) की सेवाएं प्रदान करेगा। भारत में यह अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसका उद्घाटन सीआईआई के नेशनल प्रेसिडेंट, श्री आर. दिनेश और सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी ने किया। इंदौर का सीआईआई केंद्र विश्व स्तरीय प्रथाओं को अपनाने में उद्योग की मदद करेगा और राज्य के 550 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सहायक होगा।

इस अवसर पर सीआईआई के प्रेसिडेंट एवं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के चेयरमैन श्री आर. दिनेश के साथ सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी, सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र के चेयरमैन और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री प्रवीर सिन्हा मौजूद रहे। सुश्री स्वाति सालगांवकर, डिप्टी चेयरपर्सन, सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र और प्रेसिडेंट, वीएम सालगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुनील चोरडीया, पूर्व अध्यक्ष सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र ने इंदौर में प्रेस और मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए।

श्री आर. दिनेश ने कहा कि '''सीआईआई केंद्र एक नई अवधारणा है और क्षेत्र के उद्योग के लिए एक अनूठी पहल है जो उनकी उत्कृष्टता यात्रा का समर्थन करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों को विश्व स्तरीय परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा और गुणवत्ता, कौशल, सस्टेनेबिलिटी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, टेक्नोलॉजी और समाधानों तक पहुंच बनाकर मध्य प्रदेश में उद्योग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाएगा।''

सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि 'इंदौर में सीआईआई केंद्र अपनी तरह का पहला केंद्र है और इसमें 10 सीआईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रतिनिधि कार्यालय होंगे, जिनका मुख्यालय वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है। अपने 360-डिग्री दृष्टिकोण के साथ, यह उद्योग के सदस्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और नॉलेज इनपुट, मूल्यांकन और प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए उनकी सुविधा के अनुरूप सेवा प्रदान करेगा।''शुरुआत में सीआईआई सेंटर के माध्यम से 1000 से ज्यादा उद्योगों को लाभ मिलेगा।

ओला मात्र 89,999 रुपये में अपने बिल्कुल नए ए1 X+ के साथ मिशन में तेज़ी लाएगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने #EndICEAge मिशन में तेजी लाने के लिए अपने 'दिसंबर टू रिमेंबर' अभियान की घोषणा की। इस अभियान में एकदम नया एस1 एक्स+ अब 20,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल सकेगा, जिसका मतलब एस1 एक्स+ की कीमत अब घटकर केवल 89,999 रुपये हो गई है। इस वजह से एस1 एक्स+ सबसे सस्ते 2व्हीलर ईवी स्कूटरों में से एक बन गया है, जिसे अपनाना सबके लिए आसान हो गया है। देश भर में ए1 X+ की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और यह स्कूटर काफ़ी ज़्यादा माँग में है। एस1 एक्स+ किफायती दाम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन, उन्नत तकनीकी सुविधाएँ और बेहतर सवारी गुणवत्ता देता है। यह 3kWh बैटरी के साथ आता है और 151 किमी की प्रमाणित रेंज देता है। साथ ही 6kW मोटर से चलने वाला एस1 एक्स+ 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटे है।

देश में ईवी को घर- घर पहुंचने के मकसद से कंपनी ने 3 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने 'दिसंबर टू रिमेम्बर' अभियान की घोषणा की है, जिसमें आकर्षक ऑफर और छूट योजनाओं के साथ सीजन का समापन काफ़ी शानदार रहेगा।

ओला के चीफ़ मार्केटिंग ऑफिसर, अंशुल खंडेलवाल ने कहा, 'ओला इलेक्ट्रिक ने नवम्बर महीने में लगभग 30,000 इकाइयों की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री के साथ एक नया इंडस्ट्री बेंच मार्क स्थापित किया है। लोग ईवी बड़ी आसानी से अपना सके इस बात में तेजी लाने और ईवी को सभी के लिए ज़रूरी बनाने के लिए, हाजिर हैं हम अपने नए एस1 एक्स+ के साथ, जो सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। जानीमानी आईसीई स्कूटर के बराबर कीमत के साथ, हमें विश्वास है कि एस1 एक्स+ #EndICEAge के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे स्कूटरों की लम्बी चौड़ी रेंज और उनकी आकर्षक कीमत के साथ, मेरा यह मानना है कि ग्राहकों के पास अब आईसीई उत्पाद खरीदने का कोई बहाना नहीं होगा।

आरवीएनएल को इंदौर मेट्रो के लिए 543 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सरकारी उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने सोमवार को कहा कि उसे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 543 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है। इस परियोजना के तहत इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। आरवीएनएल ने बीएसई को दी गई एक सूचना में कहा, ''इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट, पांच एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशनों के आंशिक डिजाइन और निर्माण के लिए आरवीएनएल-यूआरसी जेवी ने सबसे कम बोली लगाई है।'' आरवीएनएल रेलवे बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन से जुड़ी है। यह परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं मानव संसाधन भी जुटाती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।